श्री स० का० पाटिल :संबंधित मिनिस्ट्रीज में फाइनेंस आती है। हो सकता है कि प्राइस सपोर्ट वगैरह देना पड़ेगा। और उसके लिये करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपये की जरूरत होगी। तो यकायक यह चीज नहीं बन सकती। कमेटी बनेगी तो उसको बहुत बातों को देखना होगा। इसलिये थोड़ी देर हो रही है।

Shri Ramanathan Chettiar: May I know whether the proposed Committee's enquiry will cover not only the cash crops but also other food crops?

Shri S. K. Patil: I am talking of the whole crops, the entire agriculture. The Committee becomes necessary not because of the food crops alone but also the cash crops, the entire acreage under cultivation which is of the quantum of somewhere about 350 million acres in this country.

श्री खाबीवाला : क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि खाद्य पदार्थों का मूल्य दिन-प्रतिदिन बढ़ता जाता है और यह कमेटी अगर जल्दी से जल्दी कोई हल नहीं निकालेगी तो कीमतें बढ़ती चली जायेंगी। जैसे कि तेल का भाव तीन रुपये सेर है, अनाज का भाव, दालों का भाव, तिलहन का भाव सब बढ़ रहे हैं।

श्री स० का० पाटिल : मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं तेल। के भाव का तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मुझे तो डर है कि भाव कम हो जायेगा और किसान को सफर करना पड़ेगा। आज गेहूं और चावल का जितना भाव है उससे नीचे बिल्कुल नहीं जाना चाहिये।

Shri Basappa: Sir, studies regarding rice have shown that 71 to 77 per cent of the price has gone to the producer. May I know wheter such studies will be extended to other foodgrains also?

Shri S. K. Patil: That is the purpose of this Advisory Committee that we propose to establish.

Shri Kalika Singh: The Foodgrains Enquiry Committee headed by Shri Asoka Mehta suggested the formation of a Price Stabilisation Board. Is this proposed Committee something like that Price Stabilisation Board or is it something different from that?

Shri S. K. Patil: Much water has flowed in Jumna after that report was made. Today we are considering other things, just the opposite things.

Shri Kasliwal: The hon. Minister spoke about fixing of prices. May I know whether the prices that will be fixed will be the minimum prices or whether they will be the ceiling prices? I want to know the kind of prices that will be fixed.

Shri S. K. Patil: I just stated that it was the other way. I never said that we want to fix the prices. The question was about the committee for fixation of prices. I said that the Committee was intended not merely for fixation of prices but determining the entire pattern of agriculture in which the fixation of prices was only one element.

बिजली के उत्पादन के लिये कम शक्ति वाले टर्बाइन

*१५५४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री ८ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २४१५ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों के सुदूरस्थ स्थानों में बिजली पैदा कर के लिये कम शक्ति वाले टर्बाइन स्थापित करने के प्रस्ताव के बारे में, जिस पर विचार किया जा रहा था, क्या निश्चय किया गया है एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : केन्द्रशासित प्रदेशों तथा कुछ राज्यों में छोटे-

छोटे जलविद्युत यंत्र स्थापित करने के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था की गई है । इनसे सम्बद्ध योजनाओं की जांच-पड़ताल हो रही है । जम्मू और काश्मीर में द्वितीय योजना के अन्त तक २०-२० किलोवाट के दो यंत्र स्थापित किये गये थे । हिमाचल प्रदेश प्रशासन १५ किलोवाट के एक और यंत्र को स्थापित कर रहा है । वहां छलिया में एक यंत्र आगे ही कार्य कर रहा है ।

I shall read it in English also.

Provision has been made in the Third Plan for installation of small hydro-electric sets in certain States and Union Territories. The schemes are under investigation. Up to the end of the Second Plan, two sets of 20 KW each were installed in Jammu and Kashmir. One set of 15 KW is also being installed by the Himachal Pradesh Administration besides the one already working at Chhaila.

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने दूसरी योजना में किये गये कुछ कार्यों का विवरण दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बंध में तीसरी योजना में क्या व्यवस्था की जा रही है और उसके लिये कोई रकम निर्धारित की गयी है ?

श्री हाथी : तीसरी योजना के लिये रकम निर्धारित की गयी है । और उम्मीद है कि छोटे-छोटे एक सौ सेट हम अलग-अलग जगहों पर लगायेंगे ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, माननीय मंत्री जी ने कहा कि केन्द्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त कुछ राज्यों में भी इस बारे में काम किया जा रहा है । मैं खासतौर से उत्तर प्रदेश के पर्वतीय इलाके के बारे में जानना चाहता हूं । क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई योजनायें भेजी हैं और क्या इस सम्बंध में कोई काम किया जा रहा है ?

श्री हाथी : उत्तर प्रदेश सरकार को हमने लिखा है । उत्तर प्रदेश आसाम, मैसूर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और वैस्ट बंगाल स्टेटों को लिखा है, वे इनवेस्टीगेशन कर रही हैं ।

Shri Raghunath Singh: May I know what was the target in the Second Five Year Plan? May I also know why only four instruments have been installed in the whole period of the Second Five Year Plan, and whether this scheme has been conomical and successful in the State of Kashmir?

Shri Hathi: No targets were fixed in the beginning of the Second Five Year Plan. A Division for investigation was only set up in 1959. Two sets have been installed in Jammu and Kashmir. One has been installed in Himachal Pradesh and another one is being installed. But no targets as such were fixed in the beginning of the Second Five Year Plan. We started only in the year 1959.

Shri Raghunath Singh: I want to know whether it has been economical and successful or not.

श्रीमती कृष्णा मेहता : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जम्मू और काश्मीर में और भी कोई सेट दिये जायेंगे क्योंकि वहां तो बहुत पहाड़ी इलाका है ?

श्री हाथी : जी हां, जम्मू और काश्मीर में और भी सैट लगेंगे ।

Pandit D. N. Tiwari: The hon. Deputy Minister has named certain States to which references have been made and which have sent in their schemes. May I know why other States like Bihar have been left out?

श्री हाथी : बिहार में भी ५५ लाख का प्राक्कलन किया गया है ।

It has not been left out?

श्री पद्म देव : माननीय मंत्री जी ने कहा कि हिमाचल में एक इस किस्म की योजना चल रही है । लेकिन पांच साल से जो नोगली हाइड्रोइलेक्ट्रिक योजना चल रही है । वह पूरी नहीं होती । क्या मैं जान सकता हूं कि वह कब तक चालू हो जायेगी ।

श्री हाथी : जैसा मैंने बताया, छैला में जो योजना है वह तो चल रही है । मैंने उसको देखा है । उससे पावर जेनेरेट हो रही है और गांवों में बिजली भेजी जा रही है । मैंने देखा है कि वह तो चल रही है ।

श्री पद्म देव : मैंने तो नोगली के बारे में पूछा था ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं जी शर्मा जी को पूछने दीजिये ।

Shri D. C. Sharma: May I know if the needs of these States, especially in the hilly areas, have been assessed; if so, what is the total kilowatts of electricity required there and how far will those will be satisfied by these small turbine generators?

Shri Hathi: Really, it is not the needs of the hilly States alone. We are locating the various sites where such sets could be installed. Investigations are going ahead. We are providing Rs. 1.6 crores. These will be small sets ranging from 20 kw to 40 kw for different States. For example, in Himachal Pradesh it may be 13 or 14 sets. In Jammu and Kashmir it may be 30 sets.

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकारें इस संबंध में जो कार्यवाही कर रही हैं, उसमें केन्द्रीय सरकार उन्हें क्या सहायता दे रही है, या देना चाहती है ।

श्री हाथी : राज्यों को जो कुछ टेक्निकल असिस्टेंस चाहिये, केन्द्रीय सरकार वह जरूर देगी । हमने इस बारे में लिखा है । उसमें कोई बड़ी बात नहीं है । वहां पानी का कितना प्रवाह है, जगह कैसी है, इसके बारे में इन्वस्टीगेशन करना है । उसके बाद जो भी टेक्निकल सहायता चाहिये, वह जरूर दी जायेगी ।

भाखड़ा बांध

*१५५५. **श्री पद्म देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा बांध के बनने के कारण उजड़े हुये बिलासपुर और कांगड़ा के सब लोग बसाये जा चुके हैं ;

(ख) यदि हां, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग कितने परिवार बसाये गये हैं ; और

(ग) क्या नकद मुआवजा पाने वाले सब लोगों को पूरा मुआवजा मिल चुका है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) (क) जी, हां । उन लोगों को छोड़ कर जिन्होंने कि नई जगहों के लिये अपने पहले विचार को बाद में बदल दिया था, सभी विस्थापितों को या तो बसा दिया गया या उन्हें मुआवजा दे दिया गया है ।

(ख) जिला हिसार (पंजाब) २२४४ परिवार । जिला बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) १७८० परिवार ।

(ग) ३२,४८८ दावेदारों में से २७,२४७ दावेदारों को पूरा मुआवजा दे दिया गया है ।

I shall read it in English also.

(a) Yes, Sir. All the displaced persons have been either rehabilitated or paid compensation, with the exception of those who had subsequently changed their previous option for a new place.